

नवभारत



2

शाह ने की 119 एसपी संग बैठक

4

समान शिक्षा: महान नागरिक राष्ट्र की आधारशिला

9

जी20 अर्थव्यवस्था में भारत सबसे आगे

10

खिताब की जंग में 8 दावेदार

ऑस्ट्रेलिया से 18 समझौते

12 वर्षों में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आए हैं पीएम मोदी

30 हजार भारतीयों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने

मेलबर्न, 09 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न में आयोजित मेलबर्न सीट्स मोदी कार्यक्रम में करीब 30 हजार भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पिछले 12 वर्षों में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आए हैं और भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

पीएम ने ग्रो मोर अचीव मोर करते हुए भारतीय मूल के लोगों को प्रोत्साहित किया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रांटम



कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की. इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और साइबर सुरक्षा सहित 18 क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किये.

दोनों देशों ने वर्ष 2015 के भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु सहयोग समझौते के तहत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम निर्यात की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति भारत के स्वच्छ ऊर्जा

6 प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में दो लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं तथा भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का भी दावेदार है. उन्होंने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलियनसुप, भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा कर चुका है. पीएम मोदी ने कहा कि किसी देश में संकट के समय भारत सबसे पहले खड़ा होता है.

पिछले 12 साल में भारत ग्लोबल ब्रांड बना है

भारतीय समुदाय के लोगों संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिक देवी भव: हमारा मूल मंत्र है। भारत रुकना नहीं आगे बढ़ना चाहता है। पिछले 12 साल में भारत ग्लोबल ब्रांड बना है. हम भारतीय दूध में चीनी की तरह है। दाल सब्जी ऑस्ट्रेलिया की लेकिन तड़का भारत की उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का दूसरा 5जी मार्केट है और देश के 99 प्रतिशत जिले 5जी सर्विस से लेस है और भारत 6जी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि धमके आतंकी ठिकानों पर हुए और गुंज पूरी दुनिया में सुनी गई। भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश नहीं करता है. दुनिया आज भारत पर भरोसा करती है। हम गांव गांव को स्पोर्ट्स से जोड़ रहे हैं। भारत का 40 देशों से ट्रेड डील चल रही है। भारत पासपोर्ट देखकर मदद नहीं करता है।

मिशन को मजबूती देगी. उन्होंने बताया कि दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करेंगे तथा कोकोस (कीलिंग) द्वीप पर स्पेस ट्रेकिंग टर्मिनल स्थापित किया जाएगा.

बदलेगी श्रीराम मंदिर की व्यवस्था

- दर्शन से चढ़ावा तक होंगे बड़े बदलाव
- पास सिस्टम में भी हुआ बड़ा परिवर्तन

अयोध्या, 09 जुलाई. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था, पूजा-पद्धति, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा और प्रशासनिक प्रणाली में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी कर रहा है.

ट्रस्ट का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, अनुशासित, आधुनिक

6 चंपत, अनिल और गोपाल की सिस्टम आईडी निष्क्रिय इसी बीच ट्रस्ट ने वीआईपी और सुपान दर्शन पास जारी करने की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए हैं. पूर्व महासचिव चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिस्टम आईडी निष्क्रिय कर दी गई है, जिनके माध्यम से पहले दर्शन पास जारी किए जाते थे. वहीं, राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास को नई सिस्टम आईडी जारी कर दी गई है, जिसके माध्यम से अब दर्शन पास जारी किए जा सकेंगे.

और श्रद्धालु-अनुकूल बनाना है। इसके लिए संत समाज और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों से प्राप्त सुझावों को भी नई व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है. वहीं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड के दौरान बुधवार को आरोपियों से

महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में 11 आरोप पत्र दाखिल

नई दिल्ली, 09 जुलाई. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को महादेव ऐप सट्टेबाजी गिरोह के सिलसिले में 11 आरोपपत्र दाखिल किये जिनमें कथित भ्रष्टाचार के मामले में छह और अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े एक अलग मामले में पांच आरोपपत्र शामिल हैं.

एजेंसी ने भ्रष्टाचार के मामले में असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज अहूजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)



के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए छह आरोपपत्र दाखिल किये. सीबीआई ने गिरोह के कथित मुख्य सरगनाओं, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी पेश किए, जिनके खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल किये जा चुके थे.

एक नई शुरुआत अब साल में 365 नहीं सिर्फ 52 इंसुलिन इंजेक्शन, टाइप-1 और टाइप-2 मरीजों को राहत

भारत में पहली बार हफ्ते में एक बार इंसुलिन लॉन्च

नई दिल्ली, 09 जुलाई. डायबिटीज के मरीजों के लिए इलाज को आसान बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है. डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में हफ्ते में एक बार लगाए जाने वाले बेसल इंसुलिन (इंसुलिन आइकोडेक) को लॉन्च किया है.

कंपनी के अनुसार यह इंसुलिन टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज से प्रभावित वयस्क मरीजों के लिए तैयार किया गया है। इस नई दवा के आने से मरीजों को रोजाना इंसुलिन



इंजेक्शन लगाने की जरूरत कम हो सकती है। कंपनी का दावा है कि सालभर में लगाए जाने वाले 365 इंजेक्शन की जगह अब केवल 52 इंजेक्शन लगाने होंगे. अविगली को फ्लेक्स टच पेन डिवाइस के माध्यम से सप्ताह में एक बार दिया जाएगा. नोवो नॉर्डिस्क के अनुसार, रोजाना इंजेक्शन लगाने की चिंता के कारण कई मरीज

भारत इंसुलिन को लॉन्च करने वाला सातवां देश

कंपनी ने अविगली का 700 यूनिट वाला पैक 2,611 रुपये में लॉन्च किया है. इसकी प्रति यूनिट लागत करीब 3.73 रुपये बताई गई है. वहीं 3 मिलीलीटर वाले 2,100 यूनिट पेन की कीमत 7,833 रुपये रखी गई है. कंपनी के अनुसार यह मौजूदा दैनिक बेसल इंसुलिन की तुलना में लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक सस्ता हो सकता है. नोवो नॉर्डिस्क इंडिया के प्रबंध निदेशक विकास श्रोत्रिया ने बताया कि भारत इस इंसुलिन को लॉन्च करने वाला सातवां देश है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य इंसुलिन शुरू करने में आने वाली मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बाधाओं को कम करना है।

इंसुलिन थैरेपी शुरू करने में देरी करते हैं। कंपनी का कहना है कि साप्ताहिक इंसुलिन से मरीजों की

सुविधा बढ़ेगी और इलाज को नियमित रूप से जारी रखने में मदद मिलेगी.

नई दिल्ली, 09 जुलाई. अवैध कब्जों और नियमों की अनदेखी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते अवैध निर्माण और हालिया अग्निकांडों का जिक्र करते हुए अधिकारियों की भूमिका पर नाराजगी जताई.

कोर्ट ने पूछा कि अवैध कब्जों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कदम उठाए गए. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नांगू की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा



अधिकारियों की मिलीभगत पर जताई नाराजगी
तेस कदम नहीं उठाने पर अवमानना की चेतावनी

कि घटनाओं के बाद अक्सर केवल बिल्डरों या निजी लोगों पर कार्रवाई होती है, जबकि संबंधित

जीतू पटवारी के छोटे भाई पुलिस हिरासत में



6 पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नाना पटवारी के खिलाफ हत्या के प्रयास, बला, अंडीबाजी सहित करीब नौ आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं. वर्तमान जांच में पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है, ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा सके.

लिए पूछताछ जारी है. पुलिस ने हाल ही में इरफान खान और रानी भाई को 10.1 ग्राम

जीतू पटवारी से मिली जानकारी के आधार पर मैंने डीजीपी और इंदौर पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो उसकी सूचना परिजनों को भी दी जानी चाहिए. ऐसी परिपाटी नहीं बननी चाहिए, जो भविष्य में लोगों के लिए परेशानी का कारण बने.



विवेक तन्खा, राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता

ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था, दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई.

टैरिफ पर पुनर्विचार करे अमेरिका: भारत

नई दिल्ली 09 जुलाई. भारत ने अमेरिका से भारतीय सामानों पर प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। साथ ही भारत ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि वह ज्वरदस्तरी मजदूरी से बने उत्पादों के आयात को रोकने में नाकाम रहा है. भारत ने ओएस्टर को औपचारिक जवाब देते हुए बातचीत के लिए तैयार रहने का भी प्रस्ताव दिया है. ओएस्टर ने मार्च 2026 में जबर्न मजदूरी और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता को लेकर 60 देशों के खिलाफ सेक्शन 301 जांच शुरू की थी.

हमें जूते छोड़ने की जरूरत नहीं: डॉ. यादव



करते हैं। कांटे-बाटों में भी दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने विधायक से कहा कि 'अच्छे काम और सच्चे काम के लिए हमें जूते-चप्पल छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी

सड़क नहीं बनी तो जूते-चप्पल त्याग दूंगा

कालापिपल से विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपनी विधानसभा की खराब सड़कों का मुद्दा उठाते हुए भावुक अंदाज में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 'जब तक मेरी विधानसभा की सड़कें नहीं बनेंगी, तब तक मैं जूते-चप्पल का त्याग करता हूं। चाहे 10 साल लग जाएं, लेकिन सड़क बनने तक मैं जूते-चप्पल नहीं पहनूंगा।

निर्माणधीन इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी सेक्टर-16 में एक निर्माणधीन तीन मंजिला इमारत के ढहने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गयी, जबकि एक मजदूर को बचा लिया गया. बचाव अभियान बुधवार को शाम से अभी तक जारी है. मलबे से तीन शव बरामद किये गये और मृतकों की पहचान स्थानीय निवासी दर्जी राम (42), इमारत के मालिक के पिता राम दुआ (62) और मजदूर काफे उर्फ नूरूल (24) के रूप में हुई है. निर्माण गिरने के बारे में पहली पीसीआर कॉल शाम 4:28 बजे मिली.

यूपी वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी मिली जगह

6 कोर्ट ने दिल्ली के लाजपत नगर, साकेत और सरोजनी नगर जैसे इलाकों का सर्वे कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी, जिसमें आईआईटी दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर, तकनीकी विशेषज्ञ, एमसीडी अधिकारी और अदालत द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि शामिल होंगे. समिति क्षेत्र में निर्माण की स्थिति और सुरक्षा मानकों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. अदालत ने 20 मई के अपने पुराने आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें सुरक्षा मानकों को लेकर निर्देश दिए गए थे.

क्षेत्रों के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाती. अदालत ने सरकारी अधिकारियों की संभावित मिलीभगत पर चिंता जताते हुए नगर निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड, लखनऊ में

यूपी वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी मिली जगह

- यूपी वक्फ बोर्ड में भी होंगे गैर-मुस्लिम सदस्य
- महिलाओं और पसमांदा को भी मिलेगा प्रतिनिधित्व

लखनऊ, 09 जुलाई. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत सूत्री वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों, दो मुस्लिम महिलाओं और पसमांदा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की तैयारी है. राज्य के कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पुष्टि की है कि यूपी के नए वक्फ बोर्ड में महिलाओं और पसमांदा मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

सरकार का कहना है कि यह कदम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप उठाया जा रहा है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा समावेशी बनाना है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार सूत्री वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य



शामिल रहेंगे। इन सदस्यों में दो गैर-मुस्लिम, दो मुस्लिम महिलाएं तथा पसमांदा मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाएगा। सरकार के अनुसार नए बोर्ड के गठन के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश सूत्री वक्फ बोर्ड का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो चुका है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड का कार्यकाल अक्टूबर 2026 में पूरा होगा।

इसी को देखते हुए दोनों बोर्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा, जहां वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

6 वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 के तहत अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रावधान किया गया है. मध्य प्रदेश नई समिति में चार महिलाओं को जगह देकर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर बोर्ड का पुनर्गठन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कदम-मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 सदस्यीय बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के साथ-साथ महिलाओं को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की तैयारी-यूपी में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर चर्चा तेज है।